जाने वाली ब्याज की दर संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण
जूजि विकास बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋजों
पर ली जाने वाली ब्याज की दर
(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

राज्य	सामान्य दर
मान्ध्र प्रदेश	8.50
भसम	9.00
बिहार	8.50
गुज रात	8.75
हरियाणा	7.75
जम्मू तथा काश्मीर	7 से 8
केरल	9.25
मध्य प्रदेश	9.00
मद्रास	8.25
महाराष्ट्र	6. 5 से 9
मैसूर	9.00
उड़ीसा	9.25
पंजाब	7.75
राजस्थान	9.00
उत्तर प्रदेश	8.25
पश्चिम बंगाल	9.5 से 19.00

DECREE COURSE IN AGRICULTURE AND VETERINARY COLLEGES

4955. SHRIMATI SAVITRI SHYAM: Will the Minister of FOOD & AGRI-CULTURE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Indian Council of Agricultural Research has issued instructions to the agriculture and veterinary colleges that unless they switch over to five year degree course in agriculture after matric or its equivalent examination by July 1968, they shall cease to be eligible for grants from the Indian Council of Agricultural Research;
- (b) the estimated expenditure involved in the change over of the course from four to five years; and

(c) what percentage of this expenditure will be borne by the Central Government as matching grants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes. However the question of extending the time limit beyond July, 1968 for implementation of this recommendation is already under consideration of the Council.

- (b) The Govt. of U.P. had set up a Committee during 1966 to work out the approximate cost involved in introducing 3 years Degree course in Agriculture after Intermediate. The cost had been estimated at Rs. 50.80 lakhs in respect of existing Agricultural Colleges for aperiod of 4 years of IV Plan.
- (c) At present no provision has been made for any matching grant in the plan provisions of the Agriculture Division of the Indian Council of Agricultural Research.

पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड 4956. भी ऑकार लाल बेरवा: क्या भन तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि पत्रकार कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमण्डस पत्रकार मजूरी बीड की सिफारिशों के बारे में उनसे 5 दिसम्बर, 1967 को मिला था; भौर
- (स) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

श्रम तथा पुनर्बास मंत्री (श्री श्रम सुब लाल हाथी): (क) धौर (ल). गैर-पत्रकार मजूरी, बोर्ड की सिफारिशों में सरकार द्वारा किए गए संशोधन के बारे में दिल्ली पत्रकार कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल 5 दिसम्बर, 1967 को मुझ से मिला था। उन्हें यह सलाह दी गई कि वे प्रषिक लाभ के लिए धान्दोलन करने के बजाए सरकार द्वारा स्वीकृत कियान्विति में सहयोग दें।